भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं.**80**
दिनांक **03** फरवरी, **2020**

तेल की बढ़ती मांग

80. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री संजय सदा शवराव मांड लकः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, वर्ष **2020** के मध्य तक भारत की तेल-मांग में वृ द्ध चीन से अ धक हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने द्वारा देश में पेट्रो लयम और पेट्रो लयम उत्पादों की बढ़ती मांग से निपटने के लए नीति तैयार की है तैयार करने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने देश में कच्चे तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लए पेट्रो लयम उत्पादों का पर्याप्त भंडार बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार तेल और पेट्रो लयम उत्पादों पर निर्भरता को कम करने के लए ऊर्जा के कुछ अन्य वैकल्पिक साधनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रका शत वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 के अनुसार, कुल प्राथ मक ऊर्जा में भारत की तेल की मांग 2018 में 233 म लयन टन तेल समतुल्य (एम टी ओ ई) से बढ़कर 2025 में 305 एम टी ओ ई होने का अनुमान है, जब क चीन की तेल की मांग 2018 में 593 एम टी ओ ई से बढ़कर 2025 में 672 एम टी ओ ई होने का अनुमान है।

(ग) सरकार ने कच्चे तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से तेल और गैस का अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने, मांग प्रतिस्थापन पर जोर डालने, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण बढ़ाने, जैव ईंधनों और वैकल्पिक ईंधनों नवीकरणीय ईंधनों पर अप्रयुक्त क्षमता के मौद्रीकरण के लए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें पहलों की श्रृंखला शा मल है जैसे हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मौद्रीकरण के लए उत्पादन हिस्सेदारी सं वदा (पीएससी) के तहत छूटों, वस्तारों और

स्पष्टीकरणों से जुड़ी नीति, खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसें संग नीति, कोल बेड मथेन के शीघ्र मौद्रीकरण संबंधी नीति, नेशनल डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, तलछटीय बे सनों में गैर मूल्यां कत क्षेत्रों का मूल्यांकन, हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: मूल्यांकन एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लए नीतिगत ढांचा, तेल और गैस के लए व र्धत निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीति, मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं के तहत गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लए नीतिगत ढांचा, कोल बेड मीथेन सं वदाएं और नामांकन क्षेत्र संबंधी नीति।

सरकार ने फरवरी, **2019** में अन्वेषण और लाइसें संग नीति में मुख्य सुधार अनुमोदित कए थे ता क अन्वेषण कार्यकलापों को बढाया जा सके, घरेलू और वदेशी निवेश को आकृष्ट कया जा सके और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, कार्य कार्यक्रम को अपेक्षाकृत अ धक महत्व देकर अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, राजकोषीय और सं वदागत शर्तों का सरलीकरण करना, सरकार को कसी उत्पादन या राजस्व हिस्सेदारी के बिना तलछटीय बे सनों की श्रेणी II और III में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली लगाना, राजकोषीय प्रोत्साहनों को बढ़ाकर खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण, वपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित गैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नवीनतम प्रौद्यो गकी और पूंजी को शा मल करना, नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियों के लए सहयोग हेतु राष्ट्रीय तेल कंपनियों को और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लए अपेक्षाकृत अ धक कार्यात्मक स्वतंत्रता देना, इलेक्ट्रानिक एकल खड़की व्यवस्था सहित अनुमोदन प्र क्रयाओं को व्यवस्थित करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है।

(घ) इं डयन स्ट्रेटजिक पेट्रो लयम रिजर्व ल. (आईएसपीआरएल) ने 3 स्थानों अर्थात **(i)** वशाखापटनम (1.33 एमएमटी), **(ii)** मंगलुरू (1.5 एमएमटी) और **(iii)** पादुर (2.5 एमएमटी) में एसपीआर सु वधाएं पहले ही सृजित कर दी हैं। सरकार ने 6.5 मी लयन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल भंडारण क्षमता के साथ दो अतिरिक्त भू मगत च ानी कंदरा एसपीआर सु वधाओं के सृजन के लए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिया है।

(ङ) सरकार देश में नगर गैस वतरण (सीजीडी) नेटवर्क की कवरेज बढ़ाकर पर्यावरण अनुकूल ढुलाई ईंधन अर्थात सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मश्रण के जरिए एथेनॉल और जैव-डीजल (ईबीपी) कार्यक्रम और डीजल में जैव-डीजल के मश्रण जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लए अनेक पहल भी की हैं। देश में जैव ईंधनों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लए, सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 बनाई है।

*****